Indian Dairy Corporation and National Dairy Development Board is under consideration.

(b) No, Sir.

(c) At present there are two nominees of the Government of India on the Boards of Directors of Indian Dairy Corporation/National Dairy Development Board.

देहात की रिहायशी जमीन पर डी० डी०ए० के "दांत" शीर्षक से छपा समाचार

3317. **श्री शरद यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1986 के जनसत्ता में "देहात की रिहायशी जमीन पर डी० डी० ए० के दांत" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए इस मामले की कोई जांच करायी गई है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामवासियों को नोटिस जारी किए गए थे और यदि हां, तो ऐसे नोटिस कितनी बार तथा किस-किस तारीख को दिए गए थे :

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाये हैं यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं : और

(घ) 1984 के संशोधित कानून के अधीन ग्रामवासियों को नोटिस जारी न किए जाने के क्या कारण हैं,

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री दलबीर सिंह**) : (क) जी हां। राष्ट्रीय राजधानी के सतत विकास को देखते हुए दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए दिल्ली में भूमि का अर्जन किया जा रहा है।

(ख) भूमि के अधिग्रहण के नोटिस दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं न कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए भूमि पिछले कई वर्षों से चरणों में अधिग्रहित की गई है और भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अधिसूचनाएं व नोटिस समय-समय पर संबधित व्यक्तियों के लिए जारी किए गए हैं ।

(ग) दिल्ली के सुनियोजित विकास के अंतर्गत भूमि अधिग्रहीत की जा रही है ।

(घ) निर्धारित समय के भीतर अधिग्रहण के लिए संशोधित भू-अर्जन अधिनियम की धारा 9 तथा 10 के अंतर्गत नये नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सलाहकार बोर्डों का स्थापित किया जाना

3318. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संविधान में ऐसे क्षेत्र के निवासियों के कल्याण के लिए एक सलाहकार परिषद के नियुक्त किए जाने का उपबन्ध है, जहां अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखती हो और जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो ;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में, जहां अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखती हैं, किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सलाहकार बोड का गठन किया गया है, और

(ग) क्या बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना क्षेत्र में इस प्रकार के सलाहकार बोर्डों का गठन किया गया है; यदि हां, तो क्या बोड कारगर ढंग से कार्य कर रहे हैं, यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 में, प्रत्येक राज्य में

जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, तथा यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दें तो ऐसे किसी राज्य में भी, जिसमें अनुसूचित आदिम जातियां है किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक आदिम जाति सलाहकार परिषद स्थापित किए जाने की व्यवस्था है ।

(ख) 10 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आदिम जाति सलाहकार परिषद की स्थापना की हुई है।

(ग) बिहार में राज्य स्तर पर आदिमजाति सलाहकार परिषद का गठन किया हुआ है और क्षेत्रीय स्तरों पर ऐसी परिषदों का गठन करने के लिए कोई संविधानिक व्यवस्था नहीं है ।

झुग्गी झौंपड़ियों में रहने वाले लोग

3319. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने लोग झुग्गी झौपड़ियों में रहते हैं ;

(ख) क्या उनके लिए पेय जल, शौचालय जैसी मूल भूत सुविधाए उपलब्ध कराई गई हैं और क्या उनके बच्चों के लिए नवोदय विद्यालयों के बदले पुराने ढंग के विद्यालयों की भी व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या सरकार 1977 की योजना के उपबंधों के अनुसार 25 गज के भूखंड आबंटित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1983 में और दुबारा 1985 में किए गए सवक्षणों के अनुसार, लगभग 1,71,000 परिवार अर्थात लगभग दस लाख व्यक्ति दिल्ली में झुग्गी-झौंपड़ियों में रह रहे थे ।

(ख) झुग्गी झौंपड़ी समूहों में पेय-जल, सामुदायिक शौचालय-स्नानागार, मांगों पर प्रकाश आदि जैसी न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए दल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सातवीं योजना में एक योजना शामिल की गई है ।

दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम द्वारा झुग्गी पुनर्वास कालोनियों में पुरानी पद्धति पर स्कूल सुविधाएं संबंधी मुहैया की गई हैं । इसके अलावा विभिन्न इलाकों में चल रहे स्कूल निकटवर्ती झुग्गी झौपड़ी समूहों में रहने वाले बच्चों की शैक्षिणिक आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं ।

(ग) झुग्गी झोपड़ी निवासियों को 25 वर्ग गज के भूखंडों का आबंटन करने की योजना बन्द कर दी गई है ।

Strike by the workers of sugar industry

3320. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that workers of the Sugar Industry had gone on *strike on October 18th this year;*

(b) if so, what are their demands; and

(c) what is Government's reaction to their demands?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (c) The information is being collected by the Government.

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को ऋण

3321. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी हो जाने की स्थिति में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को, उन्हें आबंटित भूमि पर मकान बनाने के लिए समेकित ग्रामीण